



हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH

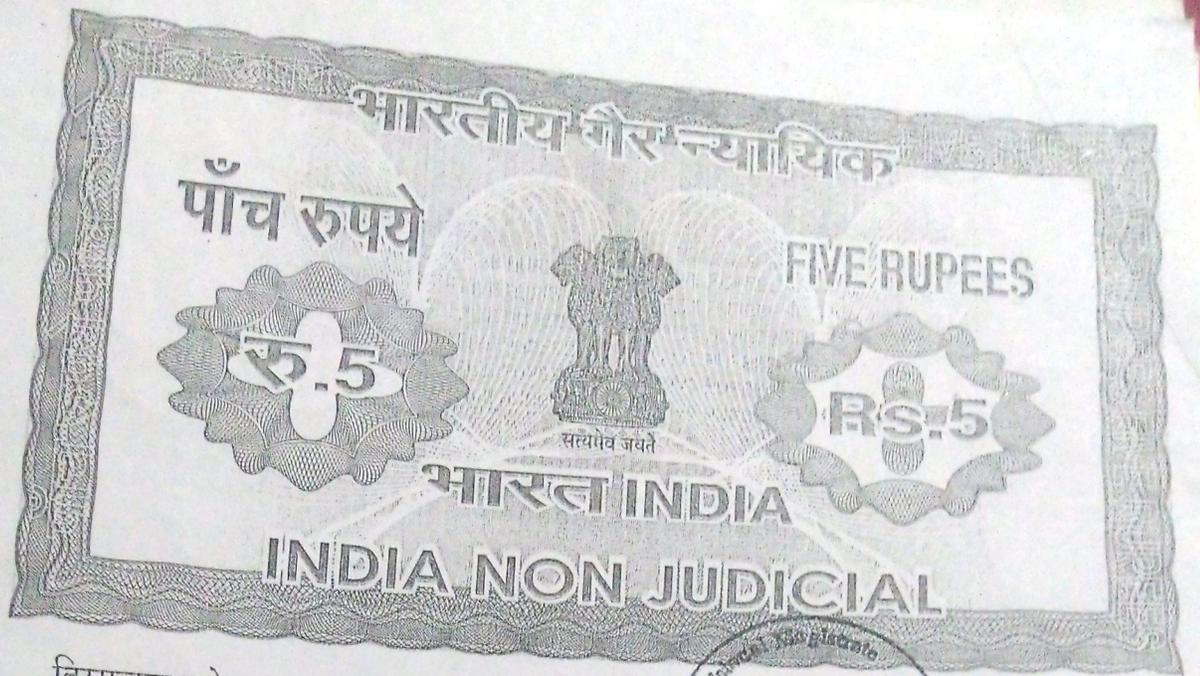
05AA 255576



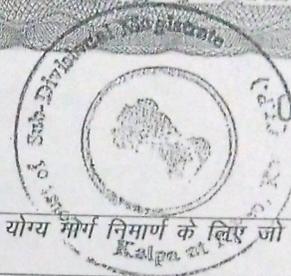
इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांक 19 माह अप्रैल सन् 2012 को ग्रामवासी ग्राम मेबर तहसील कल्पा जिला किन्नौर हि0 प्र0 (जिसे इस के पश्चात प्रथम पक्ष भी कहा जा सकेगा) बंजरिया 1) श्रीगीत लीखतारा पालोभा प्रथम ग्राम पंचायत मेबर 2) श्री कृष्ण देव शंकरा लखतारा लखतारा मेबर 3) श्री डामिन कुमार उपस्थान ग्राम पंचायत मेबर व महाप्रबन्धक एच0 पी0 पी0 सी0 एल0 शौंगठौंग-करच्छम एच0 ई0 पी0 (पोवारी-रल्ली 450 मे0 वा0) रिकांगपिओ जिला किन्नौर हि0 प्र0 (जिन्हे इस के पश्चात द्वितीय पक्ष भी कहा जा सकेगा) के बीच परस्पर सम्पन्न हुआ।

मांगों के निर्णय का विवरण	
1.	हि0 प्र0 उर्जा निगम अपने लागत पर रल्ली से बरोदार मेबर के मध्य ग्रामीणों के आवागमन हेतु (Two way passenger trolley) दोनों तरफ चलने वाली ट्राली का निर्माण करेगी और इस कार्य को HPPCL स्वयं करेगा। अनापति प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरु कर दिया जाएगा। NOC जारी करने की तिथि से 6 महीने Clearances के लिए एवं 15 महीने कार्य पूर्ण करने के लिए समय सीमा रहेगी। HPPCL गांव के अधिकृत व्यक्तियों को trolley चलाने बारे 6 महीने तक प्रशिक्षण देगी। यदि उर्जा निगम इस कार्य को करने में किसी कारण वश विफल रहती है तो निगम trolley के उस समय के वर्तमान अनुमानित लागत जिलाधीश किन्नौर के पास ग्राम पंचायत मेबर के नाम जमा करेगी।
2.	बरोदार से मेबर मन्दिर तक जीप योग्य सड़क का निर्माण करेगी, जिसकी लम्बाई लगभग 2.5 किलो मीटर है। जिसकी अनुमानित लागत 75 लाख रुपये है। निगम इस कार्य के लिए राशि किस्तों में (10 लाख, 20 लाख, 25 लाख और 20 लाख) पंचायत को मुहैया कराएगी। इस कार्य के लिए Clearances पंचायत को अपने आधार पर लेना होगा एवं निर्माण कार्य स्वयं पंचायत करेगी। इसकी पहली किस्त (Rs. 10 Lac) NOC जारी करने की तिथि से तीन महीने के भीतर जारी की जाएगी। बाकी किस्तें उपयोगिता प्रमाण पत्र (U/C) जमा करने के एक महीने के भीतर जारी की जाएगी। यदि इस राशि से सड़क का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो शेष कार्य के लिए धनराशि चरणबद्ध तरीके से



हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH



05AA 255577

3. बिना बाधा के कार्य पूर्ण होने तक निगम मुहैया कराएगी। इस जीप योग्य मार्ग निर्माण के लिए जो तकनीकी सम्बन्धी खर्चा आएगा उसका भी निगम ही वहन करेगा।
3. हि0 प्र0 उर्जा निगम के परियोजना निर्माण के कारण यदि सामुदायिक अथवा निजी सम्पत्ति को प्रमाणित क्षति होती है तो उर्जा निगम उसकी भरपाई सरकार के नियमानुसार करेगा।
4. मेबर पंचायत क्षेत्र में परियोजना निर्माण के दौरान नुकसान होने की स्थिति में निगम, ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के मनोनित सदस्य एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि (तहसीलदार के पद से कम नहीं) नुकसान का उचित पुष्टि करेगे एवं आकलन करेगे तथा नुकसान की पुष्टि होने पर निगम इसकी भरपाई आपदा होने के 3 महीने के समय काल में करेगी। जो परियोजना निर्माण के पूर्ण होने के दो वर्ष बाद तक की जाएगी। समस्या का आपसी समाधान न होने पर जिलाधीश किन्नौर के पास इसका समाधान किया जाएगा।
5. परियोजना निर्माण के दौरान प्रदूषण से बागवानी एवं कृषि में होने वाली क्षति का मुआवजा सरकार के द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार क्षति पूर्ति दावों का निपटारा किया जाएगा।
6. निगम द्वारा वन अधिकार के एवज में जो न्यूनतम 500 दिन के बराबर की राशि दी जानी है उसे सरकार के न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मासिक वित्तीय सहायता के रूप में परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। इस वित्तीय राशि को वन भूमि हस्तांतरण होने के उपरान्त जारी कर दिया जाएगा।
7. निगम द्वारा अधिग्रहण भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि सड़क एवम संसाधन प्रयोग हेतू ग्राम सभा से अनुमति ली जाएगी। अन्यथा ग्राम सभा का अपना निर्णय लागू होगा।
8. विकास कार्य के लिए 10 लाख की राशि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के उपरान्त किश्तों में जारी कर दी जाएगी।
9. हर प्रभावित परिवार को दो कमरे एवं टायलेट, तथा किचन बनाने हेतू रेटा व बजरी परियोजना का कार्य शुरु होने पर मुहैया करवाएगी। अतिरिक्त रेटा व बजरी ग्राम पंचायत के सिफारिश पर यदि कोई उचित (Genuine) आवश्यकता हो तो दी जाएगी। जिसे सबसे नजदीक के स्टोक यार्ड से दिया जाएगा।
10. निगम निर्माण कार्य में नियन्त्रित विस्फोट करेगा तथा सरकार के नियमनुसार ही कार्य करेगी।
11. आपदा प्रबन्धन एवम शिकायत निवारण समिति परियोजना का कार्य शुरु होने से पहले तथा परियोजना के पंचायत क्षेत्र में गठित कर दी जाएगी, जिसमें एक सदस्य जिला प्रशासन से, तीन सदस्य निगम से एवं उपाध्यक्ष सहित तीन सदस्य ग्राम सभा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि होंगे, गम्भीर आपदा/शिकायत होने की स्थिति में उसका निपटारा एक

	सप्ताह के भीतर किया जाएगा एवं सामान्य परिस्थितियों में शिकायत/आपदा होने की स्थिति में उसका निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर पंचायत में लगाने जायेंगे। निगम किसी भी प्रकार के परियोजना के कार्य को रोकने से सम्बन्धित शिकायत को, जिला प्रशासन या राज्य सरकार से करता है तो उसकी प्रतिलिपि पंचायत को प्रेषित की जाएगी।
12	निगम केन्द्र व राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करेगा।
13	निगम मेबर व रल्ली गांव में भूकम्प मापक यंत्र, जिस पर ग्राम सभा एवं निगम दोनों का बराबर नियंत्रण होगा, निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पहले स्थापित कर दिया जाएगा। इसके नियम भी उपलब्ध कराये जायेंगे।
14	परियोजना निर्माण की वजह से अगर पानी के स्त्रोत सूखेंगे तो उसकी भरपाई सम्बन्धित विभाग (सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग) द्वारा उचित माध्यम से की जाएगी। इसके लिये धनराशि HPPCL द्वारा दी जायेगी।
15	उपरोक्त सभी कम संख्या 1 से 14 तक पर व्यय राशि स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के अतिरिक्त होंगे।
16	मेबर दाखो मेबर रास्ता मेबर वासियों एवं देवता साहिब के आने जाने के लिए कम से कम चार फुट चौड़ा रखा जाएगा।
17	निगम इकरारनामों के अनुसार माने हुए पंचायत के मुददों पर कार्य करेगी, किसी प्रकार की असहमति होने पर पंचायत तथा सर्घष समिति के साथ बात कर आपसी सहमति से समाधान करेगी। अन्यथा ग्राम सभा शिकायत निवारण समिति के पास जाने के लिए स्वतन्त्र होगी। शिकायत के प्रयाप्त समय में निवारण न होने पर दोनों पक्ष कानूनी कार्यावाही के लिए स्वतंत्र होंगे।
18	मेबर पंचायत के इच्छुक ठेकेदारों को निगम योग्यता अनुसार एवं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुसार ही कार्य उपलब्ध करवाएगी।
19	रल्ली से मेबर पैदल मार्ग में जहां पर जरूरत होगी वहां पर आवश्यकता अनुसार रास्ता पक्का करने तथा रैलिंग के निर्माण हेतु निगम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

सर्वप्रथम ग्राम सभा मेबर की सभी शर्तें मान ली गई हैं। अतः ग्राम पंचायत मेबर एवं सर्घष समिति मेबर तथा सभी ग्राम वासी परियोजना के कार्य में पूर्ण सहयोग करेगी एवं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालेगी। यदि उपरोक्त शर्तों के अलावा 10 से ज्यादा ग्रामवासी व्यवधान डालते हैं तो यह इकरारनामा निरस्त समझा जाएगा।

यह कि उपरोक्त इकरारनामा में लिखित शर्तों के आधार पर प्रथम पक्ष/ग्राम वासी मेबर, द्वितीय पक्ष/एचओ पीओ पीओ सीओ एलओ के पक्ष में शौंगतोंग करच्छम जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अनापति प्रमाण पत्र देने को तैयार है।

अतः यह इकरारनामा दोनों पक्षों ने स्वस्थ इन्द्रियों तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में व बिना-किसी बाहरी दबाव के गवाहन के समक्ष लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आये।

आज दिनांक:-

मुकाम:- रिकांग पिओ

गवाहन:-

श्री एटी सुब्बान्त-ए-एल
सदस्य, पंचायत समिति आंका वाई

श्री परमेश्वर नगी
सदस्य, पंचायत समिति मेबर

श्री सुब्बान्त
मुकेश रीनदी
कानून आधिकारी (R&R)
शौंगतोंग-करच्छम जल विद्युत परियोजना
आंका वाई

Sr. Manager (R&R)
Shongtong-Karchham HEP,
HPPCL, Reckong Peo,
Distt. Kinnaur 172107



हरिताक्षर श्री सुब्बान्त
दिनांक 19-4-12

द्वितीय पक्ष

General Manager
Shongtong-Karchham HEP,
HPPCL, Reckong Peo,
Distt. Kinnaur (HR) 172107

SDK- 1026/2012

Attested

Sub-Divisional Magistrate
Kinnaur at R/Peo Distt. Kinnaur